Written Answers KARTIKA 14, 1887 (SAKA) Confiscation of Goods 594
and Ships by Pakisistan (C.A.)

- (ii) 10 years, and
- (iii) 5 years;
- (b) whether it is the policy of Government that such officers should not remain at a particular station continuously for such a long period so as to avoid developing undue influence; and
- (c) if so, the steps being taken to bring down the number of officers referred to above?

The Minister of State in Ministrytry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) (i) Nil.

- (ii) 14.
- (iii) 20.
- (b) and (c). The policy of the Government is that officers should not be normally retained at one place for unduly long periods. Transfers are periodically made, keeping, in administrative requirements. Among the 34 officers referred to in part (a), 17 are Administrative Officers who have to be kept at Delhi, as the Administrative posts are only in the Headquarters office at Delhi. The remaining 17 officers have mostly been transferred from one post to another in the Headquarters office or in the Divisional office and from the Headquarters office to the Divisional office and vice-versa. In a few cases, officers have to be kept in the same post for long periods on account of the specialised nature of the job.

Export of Handloom Goods

226. Shri M. Malaichami: Will the Minister of Commerce be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the total export earnings of handloom goods during 1965-66 have exceeded that of 1964-65; and
- (b) if so, whether all the accumulated stock of handloom goods has been cleared?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy): (a) The exports of handloom goods during 1965-66 (April-August) were of the order of Rs. 6·47 crores as against Rs. 4·74 crores for the corresponding period in 1964-65. The total exports of handloom goods during 1964-65 (April 1964—March 1965) were of the order of Rs. 15:04 crores.

(b) There is still some accumulation of handloom fabrics in Andhra Pradesh, Madras and Maharashtra.

12 hrs

CALLING ATTENTION TO MAT-TER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

IMPOUNDING OF INDIAN SHIPS AND CONFISCATION OF JUTE, TEA ETC. BY PARSITAN

भी बज्ञपाल लिह (कैराना) : प्रध्यक्ष महोदय, मैं भ्रविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की भ्रोर परिबहन मंत्री का ध्यान दिलाता हूं भ्रीर प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वस्तव्य दें :---

> "पाकिस्तान द्वारा भारतीय जहाजों को र्ह्हारोका जाना भीर लगभग 5.35 करोड़ रुपये के भारतीय पटसन, चाय, भादि का जस्त किया जाना तथा उस पर भारत सरकार की प्रतिकिया"।

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): I have a statement to make; it is a lengthy one; it runs over about 11 pages.

Mr. Speaker: Is he prepared to lay it on the Table of the House?

That would be circulated and then I will allow an opportunity to Members to put their questions.

Shri Raj Bahadur: I lay the statement on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-5075/651.

An hon, Member: It may be circulated today. Mr. Speaker: It cannot be circulated foday. If they are satisfied, I suggest that they may look into the statement and I will allow an opportunity later.

ग्रगर मातनीय सदस्य चाहते हैं, तो वे श्राव ही इस स्टेटमेंट को पढ़ में ग्रीप में श्राव ही सवातों के लिए मौका दे सकता हं।

श्री नाम पार्ड (राजापुर) : इस को स्रोमकार को लिया जा सकता है।

भ्रष्यक्ष महोदयः तो हम इस को सोमवार को लेलेंगे।

12.02 hrs.

RE: MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES. (Query)

डा० राम मनोहर लोहिया (प्र.कं बाबाद): मध्यक्ष महोदय,

श्राध्यक्ष महोदय: मैंने माननीय सदस्य का नोटिस रखा हुचा है। पहले प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट हो जाने दीजिये। भगर उन्होंने भ्रपने स्टेटमेंट में इस मामले को डील न किया, तो मैं बाद में इस को ले लंगा।

बार राम मनोहर लोहिया: मैं घाप का ध्यान इस तरफ़ खोंचना चाहता हूं कि प्रधान बंबी साहब प्रपना बयान दे देंगे घौर फिर उस के बाद ग्राप इस घर को बरख़ास्त कर देंगे। मुझे घोड़ा सा जिक्र कर लेने दीजिए। ग्रगर मैं ग्रंग्रेजी बोलूं, तो ग्राप मुझे बोलने देंगे। मुझे एक मिनट बोलने बीजिए।

हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के मामले में प्रधान मंत्री साहब ने मजबूरी से कुछ तो धपनी कामयाबी दिखाई, लेकिन बहुत मामलों में वह निकम्मे साबित हुए हैं। हम दो दिलों से बैठे हुए हैं, लेकिन वह बात सदय में वहीं भा पाई है। प्रधान मंत्री काली खपडी बात कहते चले जायेंचे। धाप जब को क्याब देने का नौका दे देंगे। धाखिर हम काहे के लिए यहां धाते हैं? यान लीजिए कि इस मामले में मैं धकेला ही हूं, लेकिन मुखे भी त्वव के निकम्मेपन के बारे में बात करने का मौका मिलना चाहिए, ताकि देश भ्रपनी हालत को सुधार सके । भगर भ्राप को तकलीफ़ हो रही है, तो मैं बैठ जाता हूं। मैंने भ्यानाकर्षण भस्ताव भीर स्थगन भस्ताब दिये हैं।

हिन्हुस्तान धौर पाकिस्तान के बारे में हमारी एक खास दृष्टि है, जिस के मुताबिक यह मामला हल किया जा सकता है। या तो दोनों देशों का महासंघ बनेगा, या युद्ध होगा। पिछले तेईस दिन तक लड़ाई चली। उस में सरकार की तरफ़ से निकम्मापन दिखाया गया। अब ऐसी हालत है कि जब धाम लगती है, तब कुआं खोदने की सोचते हैं, पहले से कुआं खोदने की तरफ़ ध्यान नहीं देते हैं। इन बातों को उठाने का मौका मिलना चाहिए। धभी वह मौका है। आज बाद में प्रधान मंत्री अपना बयान दे देंगे धौर धाप सदन को वरख़ास्त कर देंगे।

क्रध्यक्ष सहोदय : ग्रभी मौका नहीं है । मैंने पहले जो फ़ैसला दे दिया है, मैं उसी पर पाबन्द हं । डाक्टर साहब ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, जो मुझे प्रपने फ़ैसले से बदल सके । श्रसल में डाक्टर साहब को यह बात इस तरह उठानी नहीं चाहिए थी। जब मैं किसी धौर मेम्बर को ऐसा करने की इजाजत नहीं देता हं, तो उन को कैंस दे सकता हं। उन्होंने कहा कि वह प्रकेले हैं, शायद इसलिए मैं उन की बात नहीं मानता है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रगर वह ग्रंगेजी में बोलते. तो शायद मैं उन को मौका दे देता । ये दोनों बातें बलत हैं। क्या बाकी के हिन्दी बोलवे बाले माननीय सदस्यों को मैं रोकता हूं भीर क्या मैं सिर्फ़ अंग्रेजी बोलने वालों को ही इजाजत देवा हं ?

भी रामेश्वरानम्ब (करनाल) : प्रध्यक्षः महोदय, यह बात तो सत्य है।

चन्यक महीबय: जो कुछ माननीय सदस्य कड़वे हैं, ग्रगर मैं हमेशा उस को दिल में रखूं, को मैं हर बक्त उन से ही चक्ता रहूं।